Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

जुलाई 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड

- लैंसडौन का नाम जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित 3
- कण्वाश्रम रेस्क्यू सेंटर प्रोजेक्ट 4
- प्रदेश के 55 अस्पतालों को मिलेगा भूकंपरोधी कवच 4
- प्रदेश में मोबाइल ईसीएचएस शुरू करने की तैयारी 5
- प्रदेश के आयुर्वेद छात्रों के लिये जापान-जर्मनी में खुले नौकरी के द्वार 6
- प्रदेश में 264 करोड़ रुपए से सुधरेगी 64 पुलों की सेहत : एचपीसी की बैठक में मिली मंजूरी 7
- राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति को कैबिनेट की मंजूरी 8
- फैक्टरियों में नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं की सुरक्षा होगी मज़बूत 9
- सात पर्वतीय ज़िलों में पहली बार मिलेगा ईएसआई का लाभ, खुलेंगी डिस्पेंसरी 9
- उत्तराखंड में अब ग्रीन टेक्नोलॉजी से होगा 23 भूस्खलन ज़ोन का उपचार 10
- उत्तराखंड विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय व नवीन वेबसाइट का हुआ लोकार्पण 11
- हरेला पर्व-2023 12
- नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर 14
- उत्तराखंड में पाँच साल में आठ लाख से अधिक लोग हुए गरीबी रेखा से बाहर 16
- प्रदेश में नौकरियों में खिलाड़ियों को मिलेगा चार प्रतिशत खेल कोटा 17
- आपदा प्रबंधन पर देहरादून में होगा अंतर्राष्ट्रीय मंथन 17
- वायुमंडल की वाष्प और भाप से बनेगा पीने का पानी, रुद्रपुर में लगेगा प्रदेश का पहला प्लांट 18
- प्रदेश में अब हर साल पाँच फीसदी महँगी हो जाएंगी सरकारी सेवाएँ: यूजर चार्जेस बढ़ाने का आदेश जारी 19
- डॉ. विक्रम गुप्ता राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित 19
- मुख्यमंत्री ने उत्तराखंडी फीचर फिल्म 'पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन' का प्रोमो तथा पोस्टर का विमोचन किया 21
- दून में 13 साल बाद होगी अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस 22
- प्रदेश के सरकारी वाहनों के रखरखाव, मरम्मत व कंडम होने की स्थिति के संबंध में नया शासनादेश जारी 22
- गांवों के बच्चों को भी विज्ञान के प्रयोग करने का मिलेगा मौका, यूकॉस्ट भेजेगा मोबाइल साइंस लैब 23
- राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के तहत गिद्धों की चार प्रजातियों पर होगा अध्ययन 24
- ई-कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर 25
- उत्तराखंड/25 'बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच एक नई पहल' पुस्तक का विमोचन 26

नोट :

उत्तराखंड

लैंसडौन का नाम जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के लैंसडौन छावनी बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर विजय मोहन चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लैंसडौन नगर का नाम हीरो ऑफ द नेफा महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। छावनी बोर्ड की कार्यालय अधीक्षक विनीता जखमोला ने इसकी पुष्टि की है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि छावनी परिषद ने वर्षों पुराने छावनी नगर का नाम लैंसडौन से परिवर्तित कर जसवंतगढ़ करने का सुझाव रक्षा मंत्रालय को भेजा है। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व में छावनी बोर्ड से नाम बदलने संबंधी सुझाव मांगा था।
- उल्लेखनीय है कि जसवंत सिंह रावत का जन्म राज्य के पौड़ी ज़िले के बीरोंखाल ब्लॉक के दुनाव ग्राम पंचायत के बाड़ियूं गाँव में 19 अगस्त, 1941 को हुआ था। जिस समय वे शहीद हुए उस समय वह गढ़वाल राइफल्स की चौथी बटालियन में सेवारत थे।
- 1962 का भारत-चीन युद्ध अंतिम चरण में था। चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे तक पहुँच गए थे। जसवंत सिंह रावत सेला टॉप के पास की सड़क के मोड़ पर तैनात थे। इस दौरान वह चीनी मीडियम मशीन को खींचते हुए भारतीय चौकी पर ले आए और उसका मुँह चीनी सैनिकों की तरफ मोड़कर उनको तहस-नहस कर दिया। 72 घंटे तक चीनी सेना को रोककर अंत में 17 नवंबर, 1962 को वह वीरगति को प्राप्त हुए।
- जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

नोट :

कण्वाश्रम रेस्क्यू सेंटर प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों ?

2 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डॉ. समीर सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में मानव वन्यजीव हमलों में लगातार हो रहे इजाफा को कम करने की कड़ी में लैंसडौन वन प्रभाग के कण्वाश्रम स्थित मृग विहार को मिनी चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित करने के लिये नए सिरे से कवायद शुरू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि प्रदेश में वन्यजीव हिंसक होकर आबादी क्षेत्र में लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में तमाम क्षेत्रों में हिंसक जानवरों (खासकर बाघ और गुलदार) को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेजा जाता है, लेकिन प्रदेश में उपलब्ध रेस्क्यू सेंटर में अब शेड्यूल वन के इन प्राणियों को रखने के लिये जगह ही नहीं बची है। इसलिये अब सरकार नए रेस्क्यू सेंटर बनाने और पुरानों को विस्तार देने जा रही है।
- कण्वाश्रम स्थित मृग विहार को मिनी चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित करने के लिये सीजेडए से लगातार बातचीत की जा रही है। इसके अलावा दूसरे रेस्क्यू सेंटर को विस्तार देने की दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं।
- करीब 12 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कण्वाश्रम स्थित मृग विहार के रेस्क्यू सेंटर में तबदील होने से वन विभाग की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी।
- विदित है कि वर्ष 2018 में तत्कालीन वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने मृग विहार को मिनी जू और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित करने के लिये पहल की थी। उस दौरान इस काम के लिये केंद्र सरकार की ओर से सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी गई थी।
- इसके बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) की ओर से इस मामले में औपचारिकताओं को पूरा के लिये कहा गया था, जो वक्त रहते वन विभाग की ओर से पूरी नहीं की गई। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब वन विभाग की ओर से फिर से मृग विहार को मिनी चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित करने के लिये शासन के माध्यम से सीजेडए के साथ पत्राचार शुरू किया गया है।
- प्रदेश में राजधानी देहरादून में मालसी में स्थित देहरादून जू रेस्क्यू सेंटर को छोड़कर बाकी तीनों रेस्क्यू सेंटर हाउसफुल चल रहे हैं। इन रेस्क्यू सेंटर में एक भी शेड्यूल वन के वन्यजीव प्राणी को रखने की जगह नहीं है।
- अल्मोड़ा में स्थित चिड़ियाघर में पाँच और रेस्क्यू सेंटर में छह कुल 11 गुलदार को रखा गया है। यहाँ अब अन्य गुलदारों को रखने की जगह नहीं है।
- इसी तरह से हरिद्वार के चिड़ियापुर में स्थित रेस्क्यू सेंटर में 11 गुलदार को रखा गया है। यह भी हाउसफुल हो चुका है। नैनीताल चिड़ियाघर में स्थित रेस्क्यू सेंटर पहले ही फुल हो चुका है।
- देहरादून जू स्थित रेस्क्यू सेंटर में एक घायल गुलदार को रखा गया था, जिसे ठीक होने पर अब जंगल में छोड़ दिया गया है। फिलहाल रेस्क्यू सेंटर में एक भी गुलदार नहीं है। वैसे भी यहाँ मात्र दो ही गुलदार को रखा जा सकता है।

प्रदेश के 55 अस्पतालों को मिलेगा भूकंपरोधी कवच

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में बताया गया कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण के तहत अस्पतालों को भूकंपरोधी कवच से लैस किया जाएगा। पहले चरण में 55 स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अस्पतालों को भूकंपरोधी कवच से लैस करने की शुरुआत पर्वतीय क्षेत्रों के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित 55 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी व पीएचसी) से होगी। भूकंपरोधी भवन बनाने के तहत इन 55 स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों की रेट्रोफिटिंग की जाएगी।
- उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यूडीआरपी) के तहत वर्ल्ड बैंक इसके लिये 38.78 करोड़ रुपए खर्च करेगा।
- विदित है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश में पुराने और जर्जर हो चुके स्वास्थ्य केंद्रों के उद्धार का प्रस्ताव शासन को सौंपा गया था।
- यूडीआरपी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में ऐसे कुल 150 स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया। उसके बाद वर्गीकरण की प्रक्रिया में इनमें से 90 अस्पताल भवनों का चयन किया गया। इसके बाद अब मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में 55 स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया।
- अब इन स्वास्थ्य केंद्रों की रेट्रोफिटिंग कर इन्हें एकदम नया रूप दिया जाएगा। जहाँ पुरानी बिल्डिंग में सुधार की गुजांइश होगी, उन्हें सुधारा जाएगा, जो भवन जर्जर हालत में हैं, वहाँ नए भूकंपरोधी भवन बनाए जाएंगे।
- इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पर्वतीय क्षेत्रों में जर्जर हालात में पहुँच चुके पीएचसी और सीएचसी नए रंग-रूप में नजर आएंगे, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने में मदद मिलेगी।
- प्रदेश में रेट्रोफिटिंग के लिये कुल 90 सीएचसी और पीएचसी का चयन किया गया है। इनमें अल्मोड़ा के सात, बागेश्वर के चार, चमोली के नौ, चंपावत के चार, देहरादून के आठ, हरिद्वार के सात, पौड़ी के 12, पिथौरागढ़ के सात, रुद्रप्रयाग के छह, टिहरी के 10, ऊधमसिंहनगर के छह और उत्तरकाशी के 10 स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया है। इनमें से पहले चरण में 55 स्वास्थ्य केंद्रों का उद्धार किया जाएगा।

प्रदेश में मोबाइल ईसीएचएस शुरू करने की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड में सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल ने बताया कि प्रदेश के लगभग दो लाख पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के नज़दीक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिये पहाड़ में मोबाइल ईसीएचएस (एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम) को शुरू करने की तैयारी चल रही है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पहाड़ों में इस सुविधा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे ज़िलों से पलायन रुकेगा।
- विदित है कि सैन्य बहुल प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधा के लिये देहरादून सहित विभिन्न ज़िलों में ईसीएचएस केंद्र बने हैं, लेकिन कुछ केंद्र दूरदराज के क्षेत्रों में होने से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। खासकर वे पूर्व सैनिक केंद्र तक नहीं पहुँच पाते, जिनकी उम्र 80 साल या फिर इससे अधिक है।
- ज्ञातव्य है कि सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक के अनुसार, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की इस साल अप्रैल में नई दिल्ली में हुई बैठक में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से इस मसले को उठाया गया था।
- बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। ईसीएचएस के लिये मानक एक समान होने से भी प्रदेश में दिक्कत पेश आ रही है।
- सेना मुख्यालय की ओर से ईसीएचएस के लिये देशभर में समान मानक तय किये गए हैं। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक के मुताबिक, कम से कम 7,500 पूर्व सैनिकों की आबादी पर एक ईसीएचएस स्थापित किया जा सकता है, जबकि देहरादून ज़िले में 36,500 पूर्व सैनिक हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में उनके आश्रित हैं।
- ईसीएचएस योजना के तहत भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों और अधिकारियों के सेवानिवृत्त होते समय अंशदान के रूप में कुछ फीस जमा कराई जाती है। इसके बाद उनका ईसीएचएस कार्ड बनता है, जिस पर उनको और उनके आश्रितों को जीवनभर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। ईसीएचएस के पैनल के निजी अस्पतालों में भी उन्हें स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है।
- मैदान में 40 से 45 किमी. की दूरी कुछ देर में तय की जा सकती है, जबकि पहाड़ में इसके लिये घंटों लगते हैं। इसके अलावा पहाड़ में ट्रांसपोर्ट की भी समस्या है। पूर्व सैनिकों को घर के नज़दीक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, इसके लिये केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में राज्य के पूर्व सैनिकों की इस समस्या को उठाया गया है।

प्रदेश के आयुर्वेद छात्रों के लिये जापान-जर्मनी में खुले नौकरी के द्वार

चर्चा में क्यों ?

6 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जापान व जर्मनी से नर्सिंग और हॉस्पिटेलिटी सेक्टर में नौकरी के लिये उत्तराखंड के आयुर्वेद नर्सिंग, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म कोर्स में पासआउट छात्रों या प्रशिक्षित युवाओं की मांग का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को मिला है, जिससे वहाँ उनके लिये नौकरी के द्वार खुले गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों से नर्सिंग, योग, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में पासआउट छात्रों का ब्योरा भेजा गया है, जिन्हें कौशल एवं सेवायोजन विभाग के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उन्हें विदेशों में नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसके लिये भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त 25 निजी आयुर्वेद व पैरामेडिकल कॉलेजों से छात्रों की सूची मांगी गई है। इस संबंध में कॉलेजों को पत्र जारी किया गया।
- आयुष सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने भी परिषद को आयुर्वेद छात्रों को कौशल एवं सेवायोजन विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण देकर विदेशों में नौकरी के अवसर दिलाने के दिशा निर्देश दिये हैं।
- परिषद की रजिस्ट्रार नवर्दा गुसाईं ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाने के लिये नर्सिंग, पंचकर्म, योग और प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स में नये सत्र से नवीन पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। जल्द ही परिषद की ओर से सभी कॉलेजों को पाठ्यक्रम पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।

नोट :

- इसके अलावा इसी महीने के अंत से परीक्षाएँ शुरू की जाएंगी। जल्द ही परिषद की ओर से परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। परीक्षा के लिये नया पैटर्न तैयार किया गया है।

प्रदेश में 264 करोड़ रुपए से सुधरेगी 64 पुलों की सेहत : एचपीसी की बैठक में मिली मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

9 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त और उम्र पूरी कर चुके पुलों की सेहत सुधारी जाएगी या उन्हें बदला जाएगा। इसी संबंध में विश्व बैंक वित्त पोषित यू-प्रीपेयर परियोजना के तहत ऐसे 64 पुलों के लिये शासन ने 264 करोड़ 69 लाख 52 हज़ार रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने शासन को 74 पुलों के लिये 622.18 करोड़ रुपए (अनुमानित लागत) का एस्टीमेट सौंपा है।
- विदित है कि राज्य में आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण के तहत प्रदेश सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। इसके लिये विश्व बैंक की मदद से पहले फेज में उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यूडीआरपी) के तहत कई कामों को पूरा किया जा चुका है और कुछ परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि दूसरे फेज में यू-प्रीपेयर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
- इसी के तहत पुलों की सेहत सुधारने का यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें उन पुलों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें दिसंबर 2022 में शासन की ओर से कराए गए सेफ्टी ऑडिट में खतरनाक घोषित कर दिया गया था।
- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना को अगले पाँच साल में पूरा किया जाना है।
- ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों राज्य के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) ने उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यूडीआरपी) को हरी झंडी दे दी थी।

नोट :

- परियोजना के तहत क्षतिग्रस्त पुलों का सुधार, नए पुलों का निर्माण और मिसिंग लिंक ब्रिज का निर्माण किया जाना है। आपदा में टूट गए पुलों को परियोजना में प्राथमिकता में लिया गया है।
- प्रदेश में विश्व बैंक वित्त पोषित यू-प्रीपेयर परियोजना के तहत एचपीसी की ओर से फिलहाल 64 पुलों के लिये वित्तीय स्वीकृति मिली है। विभाग ने 74 पुलों के लिये अनुमानित खर्च की राशि का ब्योरा सौंपा है। जैसे-जैसे टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी, पुलों के सुधार का काम शुरू कराते जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2022 में शासन के निर्देश पर कराए गए सेफ्टी ऑडिट में 36 पुल असुरक्षित पाए गए थे। उस दौरान पाँच ज़ोन के 3262 का सेफ्टी ऑडिट कराया गया था। इसके अंतर्गत जिन पुलों में तकनीकी तौर पर सुधार किया जा सकता है, उन्हें ठीक कराया जाएगा।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति को कैबिनेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में नियमों और मानकों को ताक पर रखकर संचालित नशामुक्ति केंद्र और मनोरोगियों के लिये संस्थानों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में प्रदेश सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति नियमावली को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- अब राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति नियमावली के नियमों के तहत ही सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों व नशामुक्ति केंद्रों का संचालन किया जाएगा।
- संस्थानों के अलावा मनोवैज्ञानिकों, मानसिक स्वास्थ्य नर्सों, मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के अस्थायी पंजीकरण के लिये दो हज़ार रुपए शुल्क रखा गया है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का पंजीकरण निशुल्क होगा।
- एक साल के अस्थायी लाइसेंस के लिये दो हज़ार रुपए शुल्क देय होगा। उसके बाद स्थायी पंजीकरण के लिये 20 हज़ार शुल्क देना होगा।
- नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में पाँच से 50 हज़ार रुपए जुर्माना, दूसरी बार में दो लाख और बार-बार उल्लंघन पर पाँच लाख जुर्माना किया जाएगा। बिना पंजीकृत नशामुक्ति केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों पर 25 हज़ार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को पहली बार में छह माह की जेल या 10 हज़ार रुपए जुर्माना, बार-बार उल्लंघन पर दो वर्ष की जेल या 50 हज़ार से पाँच लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा।
- विदित है कि वर्ष 2019 में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सात ज़िलों में निगरानी व सुनवाई के लिये बोर्ड गठन कर दिया है। इनमें हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी ज़िले में बोर्ड बन चुका है, जबकि छह ज़िलों में प्रक्रिया चल रही है।
- राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति नियमावली के अंतर्गत नशामुक्ति केंद्र मानसिक रोगी को कमरे में बंधक बनाकर नहीं रख सकते हैं। डॉक्टर के परामर्श पर ही नशामुक्ति केंद्रों में मरीज को रखा जाएगा और डिस्चार्ज किया जाएगा। केंद्र में फीस, ठहरने, खाने का मेन्यू प्रदर्शित करना होगा।
- मरीजों के इलाज के लिये चिकित्सक, मनोचिकित्सक को रखना होगा। केंद्र में मानसिक रोगियों के लिये खुली जगह होनी चाहिये।
- ज़िलास्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड के माध्यम से निगरानी की जाएगी। मानसिक रोगी को परिजनों से बात करने के लिये फोन की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कमरों में एक बेड से दूसरे बेड की दूरी भी निर्धारित की गई है।
- इस नीति के लागू होने से राज्य के मानसिक रोगियों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में होने वाली घटनाओं पर रोक लगेगी।

नोट :

फैक्टरियों में नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं की सुरक्षा होगी मज़बूत

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में रात्रि पाली में कारखानों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिये सुरक्षा मज़बूत करने का निर्णय लेते हुए श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि कारखाना अधिनियम 1948 में महिला कार्मिकों को जो भी राहतें दी गई थीं, उसमें संशोधन करते हुए राहत और बढ़ाई गई है।
- अब कारखानों में रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाकर्मियों को घर लाने-ले जाने वाले वाहनों में पैनिक बटन, जीपीएस डिवाइस, सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा।
- इन वाहनों का संचालन करने वाली ड्राइवर-कंडक्टर का पुलिस से सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि रात्रि पाली में महिलाएँ केवल उसी कारखाने में काम कर सकेंगी, जहां कम से कम 20 महिलाकर्मी हों। इससे कम पर रात्रिपाली की अनुमति महिलाकर्मियों के लिये नहीं होगी।
- नए नियम लागू होने पर महिलाओं को घर से कारखाने में आवागमन आसान हो जाएगा।

सात पर्वतीय ज़िलों में पहली बार मिलेगा ईएसआई का लाभ, खुलेंगी डिस्पेंसरी

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सात पर्वतीय ज़िलों में पहली बार बीमित कार्मिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी) का लाभ देने के लिये निदेशालय इन सात ज़िलों में डिस्पेंसरी खोलेगा। वहीं, प्रदेश में तीन नए शहरों में भी ईएसआई के अस्पताल खुलने जा रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार इन सात पर्वतीय ज़िलों में डिस्पेंसरी खुलने से 50 हज़ार बीमित कार्मिकों के परिजन सहित दो लाख लोगों को निशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी।

नोट :

- निदेशालय के मुताबिक, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर में अभी तक ईएसआईसी बीमित कार्मिकों व उनके परिजनों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिये मैदानी ज़िलों में आना पड़ता था। श्रम विभाग के आँकड़ों के मुताबिक, इन सात ज़िलों में अभी तक 50 हज़ार बीमित कर्मचारी हैं। हालाँकि, इन ज़िलों के तमाम लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। ऐसे में उनके परिजन पहाड़ में ही ईएसआईसी का लाभ ले सकेंगे।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना की ओर से हरिद्वार में 300 बेड का अस्पताल बनवाया जा रहा है, जिसमें 250 बेड स्पेशलिटी और 50 बेड सुपर स्पेशलिटी के होंगे। यह अस्पताल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद ईएसआई बीमित कर्मचारियों को पहली बार अत्याधुनिक और महंगा इलाज निशुल्क मिलेगा।
- वहीं, देहरादून में ऋषिकेश-रायवाला के बीच में ईएसआई का 100 बेड का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव ज़िलाधिकारी को भेजा गया है। दूसरी ओर, काशीपुर में भी शहर के निकट ही 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बनाने का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। अभी तक प्रदेश में ईएसआई का केवल एक अस्पताल रुद्रपुर में है।
- विदित है कि कंपनियों, फैक्ट्रियों या अन्य संस्थानों में काम करने वाले करीब सात लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो कि ईएसआई के दायरे में आते हैं। इनके परिजनों को मिलाकर ईएसआई से स्वास्थ्य लाभ लेने वालों की संख्या करीब 28 लाख है।
- ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार और नैनीताल में पहले से चल रही 10 डिस्पेंसरी के पते बदलने जा रहे हैं। निदेशालय ने नई जगहों पर किराये के भवन में बदलाव की विज्ञप्ति जारी की है। इसके तहत ऊधमसिंहनगर ज़िले के सितारगंज, बाजपुर, जसपुर व रुद्रपुर में, हरिद्वार के भगवानपुर, हरिद्वार व सिडकुल बहादराबाद में और नैनीताल के लालकुआँ, हल्द्वानी, नैनीताल में डिस्पेंसरी नए भवन में शिफ्ट की जाएंगी।

उत्तराखंड में अब ग्रीन टेक्नोलॉजी से होगा 23 भूस्खलन ज़ोन का उपचार

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के लिये नासूर बन चुके क्रॉनिक लैंडस्लाइड ज़ोन के उपचार की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब बॉयो-इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए ऐसे भूस्खलन क्षेत्रों का ग्रीन टेक्नोलॉजी से उपचार किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- वर्ल्ड बैंक वित्त पोषित यू-प्रीपेयर परियोजना के तहत इस काम के लिये प्रथम चरण में 100 करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं।
- पहले चरण में विभिन्न पर्वतीय ज़िलों में 23 क्रॉनिक लैंडस्लाइड ज़ोन को चिह्नित किया गया है।
- विदित है कि प्रदेश में मानसून सीजन में हर साल सक्रिय होने वाले लैंडस्लाइड ज़ोन प्रदेश के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं। सड़कों के बंद होने से जहाँ आवाजाही बाधित होती है, वहीं पूरा जनजीवन प्रभावित होता है। राज्य सरकार भूस्खलन से बंद हुए मार्गों को खोलने में हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन हर बार फिर वही स्थिति बन जाती है। इसीलिये ही प्रदेश सरकार ने अब इनके स्थायी उपचार का निर्णय लिया है।
- विश्व बैंक वित्त पोषित यू-प्रीपेयर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में बनी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की ओर से 23 सक्रिय भूस्खलन ज़ोन के ट्रीटमेंट की अनुमति दी गई है।
- इनमें चमोली में एक, अल्मोड़ा में एक, नैनीताल में छह, पौड़ी में चार, टिहरी में चार, उत्तरकाशी में चार और रुद्रप्रयाग में तीन स्थानों पर क्रॉनिक लैंडस्लाइड ज़ोन का उपचार किया जाएगा।
- इसके लिये बॉयो-इंजीनियरिंग तकनीक के तहत ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कंकरीट, सीमेंट और जाल के साथ विशेष प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाता है, ताकि मिट्टी-पत्थर और चट्टानें हमेशा के लिये स्थिर हो जाएँ।

नोट :

उत्तराखंड विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय व नवीन वेबसाइट का हुआ लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड के विधानसभा सभागार में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय व नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया, जिससे विधानसभा के विधायी कार्यों, सदन की कार्यवाही से संबंधित जानकारी अब एक क्लिक पर मिल सकेगी।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा, विधानसभा में ई-लाईब्रेरी से देश-विदेश के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक व शोध पर आधारित पुस्तक उपलब्ध होंगी।
- पुस्तकालय में लगभग 25 हज़ार से ऊपर पुस्तकों का समावेश किया गया है, जिसमें संविधान एवं कानून, लोक प्रशासन और सामान्य ज्ञान समेत विभिन्न विषयों से संबंधित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। पुस्तकें डिजिटल और प्रिंट दोनों रूप में उपलब्ध होंगी।
- विधानसभा पुस्तकालय से विधायकों को संसदीय कार्यों में सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पुस्तकालय में उपलब्ध विशिष्ट पुस्तकों के अध्ययन से उन्हें सामाजिक कार्यों में भी लाभ होगा।
- विधानसभा में इस पुस्तकालय के माध्यम से सभी निर्वाचित सदस्य अपनी संसदीय समस्याओं के समाधान के साथ ही संसदीय परंपराओं एवं सदन के भीतर होने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों से कार्यसूची के अनुसार सदन की कार्यवाही की जानकारियाँ व पुराने अभिलेखों से अनेक लोगों का मार्गदर्शन होगा।
- इस पुस्तकालय को देश की अन्य विधानसभाओं की लाइब्रेरी संसद की लाइब्रेरी से भी जोड़ा जाएगा।
- विधानसभा की नई वेबसाइट www.vidhansabha.gov.in पर लोगों को विधायी व सदन की कार्यवाही व प्रश्न-उत्तर एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे।

नोट :

हरेला पर्व-2023

चर्चा में क्यों ?

17 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग की ओर से देहरादून के रायपुर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित हरेला पर्व का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास करने वाले स्कूलों और वनपंचायतों को सम्मानित भी किया।
- वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हरेला पर्व के उपलक्ष्य में इस वर्ष प्रदेश में आठ लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा।
- उन्होंने पौध रोपण के साथ ही उनके संरक्षण की दिशा में भी विशेष ध्यान दिये जाने की बात कही। जिस सेक्टर में वृक्षों का सक्सेस रेट सबसे अधिक होगा, उस सेक्टर के वन दरोगा को सम्मानित किया जाएगा।
- प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने कहा कि 15 अगस्त को 1750 गाँवों में 75-75 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से अपील की कि पर्यावरण के संरक्षण में सभी एकजुट होकर कार्य करें और पौधे लगाकर सेल्फी विद प्लांट पोस्ट करें, जिससे हम अपनी भावी पीढ़ी को बता सकें कि हमने पर्यावरण संरक्षण के लिये क्या योगदान दिया।
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। यहाँ का हरेला पर्व सुख, समृद्धि, शांति, पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। यह पर्व सामाजिक सद्भाव का पर्व और ऋतु परिवर्तन का भी सूचक है। हरेला एक ऐसा ही पर्व है, जो हमारी प्रकृति से निकटता को और अधिक प्रगाढ़ बनाता है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी पर काफी जोर दिया है क्योंकि जल संरक्षण के क्षेत्र में भी सर्कुलर इकोनॉमी की बड़ी भूमिका है। जब ट्रीटेड जल को फिर से उपयोग किया जाता है, ताजा जल को संरक्षित किया जाता है तो उससे पूरे ईको सिस्टम को बहुत लाभ होता है।

नोट :

वभूमि दर्शन
उत्तराखंड के लोकपर्व
हरेला की
हार्दिक शुभकामनाएं
जी रये जागी रये,
यो दिन यो बार भेंटने रये।
दुब जस फैल जाए,
बेरी जस फली जाईये।
हिमाल में ह्युं छन तक,
गंगा ज्यूँ में पाणी छन तक,
यो दिन और यो मास
भेंटने रये।।
hoomidarshan.in

मनायें

नोट :

नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

17 जुलाई, 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने देश के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिये 'निर्यात तैयारी इंडेक्स (ईपीआई) 2022' नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया, जिसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।

प्रमुख बिंदु

- ईपीआई 2022 रिपोर्ट में क्षेत्र विशिष्ट अंतर्दृष्टि के साथ निर्णय लेने में सहायता करने, मज़बूती की पहचान, कमियों को दूर करने और भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में बड़े पैमाने पर वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकारों को अधिकार दिये जाने की वकालत की गई है।
- रिपोर्ट वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के निर्यात कारोबार का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें क्षेत्र-विशेष के साथ ही ज़िला स्तर पर वस्तु निर्यात के रुझान भी शामिल हैं।
- ईपीआई 2022 रिपोर्ट राज्यों के प्रदर्शन का चार स्तंभों में मूल्यांकन करती है- नीति, व्यावसायिक परिवेश, निर्यात इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन।
- इंडेक्स में 56 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है जिनसे राज्यों और यूटी की निर्यात मामले में राज्य व ज़िला दोनों स्तर पर निर्यात तैयारियों की समग्र तस्वीर सामने आ जाती है।
- इंडेक्स में चार स्तंभों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -
  - नीति स्तंभ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य और ज़िला स्तर पर निर्यात से जुड़े नीतिगत इकोसिस्टम और इसके इर्द-गिर्द खड़ी संस्थागत संरचना पर आधारित मूल्यांकन किया जाता है।
  - व्यावसायिक परिवेश में कारोबार को समर्थन देने वाली ढाँचागत सुविधाओं, राज्य/यूटी परिवहन संपर्क के साथ ही राज्य/यूटी में मौजूदा व्यावसायिक परिवेश का आकलन किया जाता है।
  - निर्यात इकोसिस्टम में निर्यातकों को दिया जाने वाला व्यापार समर्थन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये राज्य में व्याप्त अनुसंधान और विकास कार्यों के साथ राज्य में निर्यात से जुड़ी ढाँचागत सुविधाओं पर गौर किया जाता है।
  - निर्यात प्रदर्शन एक आउटपुट आधारित संकेतक है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले राज्य की निर्यात वृद्धि को मापा जाता है और उसके निर्यात केंद्रित कार्यों और वैश्विक बाज़ार में उपस्थिति को आंका जाता है।
- ये स्तंभ आगे दस उप-स्तंभों पर आधारित हैं- इनमें निर्यात संवर्द्धन नीति, संस्थागत रूपरेखा ढाँचा, व्यावसायिक परिवेश, ढाँचागत सुविधाएँ, परिवहन संपर्क, निर्यात सुविधाएं, व्यापार समर्थन, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, निर्यात में विविधता और वृद्धि को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हैं।
- ईपीआई रिपोर्ट 2022 में देखा गया है कि ज्यादातर 'तटीय राज्यों'ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात पूरे देश में सभी श्रेणी के राज्यों में निर्यात तैयारियों के मामले में सबसे आगे रहे हैं।
- उत्तराखंड ने निर्यात तैयारी सूचकांक में लंबी छलांग लगाई है। इस सूचकांक रैंकिंग में राज्य ने सुधार कर देश में नौवां स्थान हासिल किया है, जबकि निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 की रैंकिंग में उत्तराखंड देश भर में 19वें स्थान पर था।
- वहीं हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड के बाद दूसरे स्थान पर हिमाचल और तीसरे स्थान पर मणिपुर है।
- विदित है कि राज्य ने नई निर्यात और लॉजिस्टिक नीति लागू भी की है। इसके अलावा, निर्यात बढ़ाने के लिये प्रत्येक ज़िले में दो उत्पादों का चयन किया है।
- ज़िला स्तर पर भी निर्यात के लिये बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं को मज़बूत किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड ने सूचकांक रैंकिंग में देश भर में नौवाँ स्थान हासिल किया, जबकि तमिलनाडु पहले और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कई सुधार किए हैं। राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट विकसित किया गया है। पंतनगर और काशीपुर में एकीकृत कंटेनर डिपो और पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क हैं।

नोट :

- राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिये टर्बो फ्यूल में 18 प्रतिशत की कमी की गई है।
- राज्य में अरोमा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, फार्मा सिटी-दो, प्लास्टिक पार्क विकसित किये जा रहे हैं।
- प्रदेश से फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, वनस्पति उत्पाद, शहद, खाद्य पदार्थ, खनिज उत्पाद, रसायनिक उत्पाद, प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी से बने उत्पाद, कपड़ा, परिवहन संबंधित उत्पाद, रक्षा संबंधी औजार का प्रमुख रूप से निर्यात किया जाता है।
- राज्य में अल्मोड़ा में अचार, प्राकृतिक रेशे, ताम्र शिल्प, बागेश्वर में ऑर्गेनिक ऊन, चंपावत में लौह बर्तन, डेयरी उत्पाद, उत्तरकाशी में सेब, चमोली में मछली व जड़ी-बूटी, देहरादून में मक्का उत्पाद, फार्मा, हरिद्वार में गन्ना उत्पाद, ऑटोमोबाइल, फार्मा, नैनीताल में ऐपण शिल्प, पौड़ी में काष्ठ शिल्प, मल्टी ग्रेन, पिथौरागढ़ में कार्पेट, रुद्रप्रयाग में शहद, जड़ी बूटी, टिहरी में मसाला, ऊधमसिंह नगर में बेकरी उत्पादन, चावल, मैंथा का निर्यात बढ़ाया जाएगा।

प्रदेश में वर्ष वार निर्यात की स्थिति:	
वर्ष	**निर्यात (करोड़ रुपए में)**
2014-15	8509
2015-16	7350
2016-17	6011
2017-18	10837
2018-19	16285
2019-20	16971

नोट :

उत्तराखंड में पाँच साल में आठ लाख से अधिक लोग हुए गरीबी रेखा से बाहर

चर्चा में क्यों ?

17 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि वर्ष 2015-16 और 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के पाँच साल के दौरान उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी में आठ फीसदी कमी आई है।

प्रमुख बिंदु

- इस तरह 2011 की जनगणना की आबादी के हिसाब से उत्तराखंड में 815,247 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
- विदित है कि नीति आयोग ने दो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) के तुलनात्मक विश्लेषण के जरिये ये रिपोर्ट तैयार की है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 और 2019-21 के बीच उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 17.67 प्रतिशत से गिरकर 9.67 प्रतिशत हो गई है। इस तरह कुल आठ प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की बहुआयामी गरीबी में 11.03 प्रतिशत की कमी आई। 2015-16 में 21.87 प्रतिशत गरीब थे, जो घटकर 2019-21 में 10.84 रह गए।
- गांवों की तुलना में राज्य के शहरी क्षेत्रों में कम गरीबी है। 2015-16 और 2019 के बीच शहरों में बहुआयामी गरीबी में 9.89 प्रतिशत गिरकर सात फीसदी रह गई।
- गरीबी को कम करने में पोषण में सुधार, स्कूली शिक्षा, स्वच्छता, खान पकाने के ईंधन की सुलभता, बिजली, आवास, परिसंपत्ति, बैंक खाते, बाल एवं मातृ मृत्यु दर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- अल्मोड़ा ज़िले में सबसे अधिक 16.18 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी में 14.74 प्रतिशत लोग गरीबी से उबरे। तीसरे स्थान पर 12.82 प्रतिशत की गिरावट के साथ चंपावत, 12.49 गिरावट के साथ चौथे पर बागेश्वर ज़िला रहा।
- इनके अलावा ऊधमसिंह नगर ज़िले में 11.72 प्रतिशत, टिहरी गढ़वाल में 11.60 प्रतिशत, चमोली में 9.96 प्रतिशत, रुद्रप्रयाग में 8.77 प्रतिशत, हरिद्वार में 8.41 प्रतिशत, पिथौरागढ़ में 7.48 प्रतिशत, देहरादून में 3.86 प्रतिशत, नैनीताल में 3.31 प्रतिशत और पौड़ी गढ़वाल ज़िले में 3.01 प्रतिशत गरीब कम हुए।

नोट :

प्रदेश में नौकरियों में खिलाड़ियों को मिलेगा चार प्रतिशत खेल कोटा

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी सीधी भर्ती के पदों पर चार प्रतिशत क्षैतिज खेल कोटा देने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। जल्द ही कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आएगा।

प्रमुख बिंदु

- वहीं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न छह विभागों में 2000 से लेकर 5400 ग्रेड पे तक के पदों पर सीधे नौकरी मिलेगी।
- विदित है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को ग्रेड पे 2000 के पद पर नौकरी दिये जाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने पूर्व में यह कहते हुए लौटा दिया था कि इस ग्रेड पे के पद पर नौकरी नहीं दी जा सकती। हालाँकि वित्त विभाग ने ओलंपिक में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को समूह 'ख' के पदों पर नियुक्ति देने पर सहमति जताई थी।
- विभाग की ओर से खेल श्रेणी दो में ओलंपिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को ग्रेड पे 4800 एवं रजत व कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को ग्रेड पे 4600 के पदों पर नौकरी देने की बात हुई थी।
- खेल श्रेणी तीन में सैफ खेल व राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों को एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप के प्रतिभागी खिलाड़ियों को समूह 'ग' के पदों पर रखे जाने की सहमति दी थी, लेकिन ग्रेड पे 2000 के पद पर नौकरी का मामला लटक गया था।
- बैठक में इन पर भी बनी सहमति:
  - महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पाँच प्रतिशत कोटा।
  - ऊधमसिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना के लिये चिन्हित की गई भूमि की उपयोगिता की जाँच का निर्णय।
  - सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था।
  - दिव्यांगों के लिये खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।
  - हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की भूमि के लिये वन विभाग के साथ होगी बैठक।
  - ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन किये जाएंगे।
  - शराब व बीयर की बोतल पर एक रुपए की धनराशि सेस के रूप में आबकारी विभाग कटौती कर रहा है। इसे खेल विभाग को दिया जाएगा। इसकी अधिसूचना के लिये कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा।
  - पौड़ी स्थित रांसी में निर्माणाधीन स्टेडियम हाई एल्टीट्यूट सेंटर के रूप में विकसित होगा।

आपदा प्रबंधन पर देहरादून में होगा अंतर्राष्ट्रीय मंथन

चर्चा में क्यों ?

23 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सहित कई राज्यों में नवंबर में आपदा प्रबंधन पर छठी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस प्री कॉन्फ्रेंस होगी। देहरादून में प्री कॉन्फ्रेंस चार अगस्त को आयोजित होगी, इसकी तैयारी शुरू हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- इंटरनेशनल डिजास्टर सोसाइटी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) संयुक्त रूप से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 28 नवंबर से एक दिसंबर के बीच करेंगे।

नोट :

- इसमें दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, छात्र, शोधार्थी शामिल होंगे। यूकॉस्ट इस कॉन्फ्रेंस का वैज्ञानिक एवं तकनीकी समन्वयक है।
- यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. दुर्गेश पंत ने बताया कि जून माह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कॉन्फ्रेंस का पोस्टर जारी किया था।
- देहरादून में चार अगस्त को पहली प्री कॉन्फ्रेंस होने के बाद नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में प्री कॉन्फ्रेंस होंगी।
- इस कॉन्फ्रेंस का विषय स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रिसाइलेंस है। विभिन्न राज्यों व देशों में अपनाई जा रही तकनीकों से दूसरे देशों में भी आपदा प्रबंधन आसान होगा।
- जापान ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफी काम किया है। उनकी मशीनें भी इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित की जाएंगी। सभी देशों को इसके लिये आमंत्रण भेजा जा चुका है। विभिन्न कारणों से नदियां जब रास्ता बदलती हैं, तो इससे भी काफी जन-धन की हानि होती है। इस पर भी सम्मेलन में विशेषज्ञ चर्चा करेंगे।
- विदित है कि आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन पर होने वाली छठीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में विश्वभर के विशेषज्ञ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग प्रतिभाग करेंगे।

वायुमंडल की वाष्प और भाप से बनेगा पीने का पानी, रुद्रपुर में लगेगा प्रदेश का पहला प्लांट

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित करने वाली रुद्रपुर ग्रीन एनर्जी कंपनी अब रुद्रपुर में वायुमंडल की वाष्प और भाप से पीने का पानी बनाने का प्लांट भी लगाएगी। कंपनी के अधिकारी प्लांट लगाने के लिये रुद्रपुर नगर निगम के मेयर व नगर आयुक्त से चर्चा कर चुके हैं।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार कचरे से सीएनजी और सीएनजी से बिजली बनाने के बाद अब रुद्रपुर ग्रीन एनर्जी कंपनी वायु से पीने का पानी बनाने की पहल करने जा रही है। इसके लिये कंपनी ने एरो वाटर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध कर लिया है।
- रुद्रपुर ग्रीन एनर्जी कंपनी के निदेशक समीर रेगे और परियोजना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि आधुनिक तकनीक के दौर में अब वाष्प, भाप और नमी से पीने का पानी बनाने का प्लांट लगने लगा है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर जीवन में कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं होगी।
- उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से लगने वाले प्लांट को लेकर रुद्रपुर नगर निगम से संपर्क किया गया है। हालाँकि अभी मेयर रामपाल और नगर आयुक्त विशाल मिश्रा प्लांट को लगाने के लिये उच्चाधिकारियों से विचार कर रहे हैं।
- कंपनी की ओर से रुद्रपुर की कल्याणी नदी की सफाई व उसका जीर्णोद्धार करने के लिये भी परियोजना बनाई गई है। कल्याणी नदी के समीप जगह-जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से वह स्वच्छ हो सकती है।
- अधिकारियों ने बताया कि कंपनी की ओर से किसानों के लिये खाद के खर्चे को कम करने के लिये कल्याणी ब्रांड के तहत तरल खाद कम्युनिटी टैंक लॉन्च करने की भी परियोजना बनाई है। शहर के विभिन्न स्थलों पर खाद केंद्र बनाए जाएंगे।
- रुद्रपुर ग्रीन एनर्जी कंपनी के परियोजना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर की तकनीक से कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की गई है। पहले चरण में परियोजना की क्षमता प्रतिदिन 20 टन गीले बायोडिग्रेडेबल कचरे का उपयोग करते हुए कंप्रेस्ड बायोगैस के साथ सूखा और तरल जैविक खाद का उत्पादन किया जा रहा है। जल्द ही प्लांट की क्षमता 50 टन गीले कचरे से सीएनजी बनाने तक की है।
- बायोगैस का उपयोग खाना बनाने और बिजली उत्पादन के लिये किया जाएगा। कंप्रेस्ड बायोगैस का उपयोग परिवहन के लिये वाहन के ईंधन के रूप में किया जाएगा।

नोट :

प्रदेश में अब हर साल पाँच फीसदी महँगी हो जाएंगी सरकारी सेवाएँ: यूजर चार्जेस बढ़ाने का आदेश जारी

चर्चा में क्यों

22 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में दी जा रही सरकारी सेवाओं के एवज में वसूले जा रहे उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्जेस) अब हर साल पहली अप्रैल को पाँच फीसदी महँगे हो जाएंगे। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि उपयोगकर्ता शुल्क का आशय ऐसे किसी भी शुल्क से है, जिसे विभिन्न विभाग या एजेंसियों के माध्यम से वसूला जा रहा है।
- आदेश में कहा गया है कि नियमित रूप से शुल्क में कम बढ़ोतरी से लोगों पर एकमुश्त बोझ नहीं पड़ेगा और जनसेवाओं की मरम्मत और देखरेख के लिये धनराशि भी प्राप्त होती रहेगी। अभी तक विभागों के स्तर पर तीन से पाँच वर्ष के अंतराल में उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने की प्रवृत्ति थी, जो एकमुश्त अधिक दिखाई देता था।
- सभी विभागों को अपने-अपने वेब पोर्टल एप के माध्यम से यूजर चार्ज लेने के लिये यूपीआई की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। आदेश में उपयोगकर्ता शुल्क की दरों को प्रचलित बाज़ार की महँगाई से जोड़ना आवश्यक बताया गया है।
- यूजर चार्ज की बढ़ोतरी दर को पाँच फीसदी से कम करने का अधिकार केवल प्रदेश मंत्रिमंडल को होगा। वह औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर संशोधित दरों को कम कर सकता है।
- आदेश के मुताबिक, यदि किसी सेवा का यूजर चार्जेस न्यूनतम पाँच फीसदी से अधिक बढ़ाना औचित्यपूर्ण व व्यावहारिक हो तो विभाग इसके लिये सक्षम होंगे। संशोधित दरें इस तरह से लागू होंगी कि इकाई के संचालन की लागत और अपग्रेडेशन लागत वहन हो सके।
- गौरतलब है कि अस्पतालों में पर्ची शुल्क, रोगों की जाँच का शुल्क, ड्राइविंग लाइसेंस व उसका रिन्यूवल, आरसी, वाहनों का ट्रांसफर, आय प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, खाता-खतौनी की नकल, रजिस्ट्री की नकल, पेयजल बिल, समेत कई अन्य विभागीय सेवाओं के एवज में यूजर चार्ज वसूला जाता है, जो पहली अप्रैल को पाँच फीसदी बढ़ जाएगा।
- वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, संपत्ति कर भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल को पाँच फीसदी बढ़ जाएगा। इसके लिये वित्त विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।

डॉ. विक्रम गुप्ता राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक भव्य समारोह में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वैज्ञानिक डॉ. विक्रम गुप्ता को खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार- 2022 (एनजीए) प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार- 2022 (एनजीए) में देश भर के कामकाजी पेशेवरों और शिक्षाविदों सहित 22 भूवैज्ञानिकों ने तीन श्रेणियों-लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिये एक राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, एक राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार और भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में आठ राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के तहत सम्मान हासिल किया।
- लाइफटाइम अचीवमेंट के लिये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉ. ओम नारायण भार्गव (मानद प्रोफेसर भूविज्ञान विभाग पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़) को दिया गया। वह पिछले चार दशकों में हिमालय में अपने उल्लेखनीय कार्य के लिये जाने जाते हैं।
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमिय कुमार समल को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने भारतीय सतह के विभिन्न आर्कियन क्रेटन के नीचे उप-महाद्वीपीय लिथोस्फेरिक मेंटल (एससीएलएम) की विविधता को समझने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

नोट :

- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वैज्ञानिक डॉ. विक्रम गुप्ता को एप्लाइड भूविज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक खतरों की जाँच जिसमें भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और सुनामी जैसे प्राकृतिक खतरों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन शामिल हैं, के लिये डॉ. सईबल घोष (उप-महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता) के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया।
- डॉ. विक्रम गुप्ता को प्राकृतिक खतरों, विशेषकर हिमालयी इलाके में भूस्खलन के क्षेत्र में अध्ययन में योगदान के लिये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार (एनजीए) से सम्मानित किया गया है।
- डॉ. विक्रम गुप्ता ने हिमालयी रीजन में भूस्खलन के बड़े हॉट स्पॉट व संभावित भूस्खलन के स्थलों का पता लगाया है। ये ऐसे बड़े भूस्खलन जोन हैं, जो अपने साथ बहने वाली नदी पर अस्थायी बांध बनाकर आबादी के लिये बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। हिमाचल के सतलुज में इस तरह का अध्ययन करने के बाद अब वह उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी में भी अध्ययन को विस्तार दे रहे हैं। अब तक भूस्खलन पर उनके 85 से अधिक पेपर अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कि 1966 में शुरू हुये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार (एनजीए) उन असाधारण लोगों और संगठनों के लिये सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक है, जिन्होंने भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता, समर्पण और नवाचार का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार खनिजों की खोज और अन्वेषण, बुनियादी भूविज्ञान, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान और खनन, खनिज अधिशोधन और सतत् खनिज विकास के क्षेत्र में प्रदान किये जाते हैं।
- राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022 के लिये कुल 173 नामांकन प्राप्त हुये थे। तीन पुरस्कार श्रेणियों के तहत वैध नामांकनों की संख्या 168 है। कुल 12 पुरस्कारों में से एएमए ने अंततः 10 पुरस्कारों का चयन किया है, जिनमें 4 व्यक्तिगत पुरस्कार, 3 टीम पुरस्कार और 3 संयुक्त
- पुरस्कार शामिल हैं। 4 व्यक्तिगत पुरस्कारों में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के वास्ते एक पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार के लिये एक अन्य पुरस्कार भी शामिल हैं।

क्र. सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या
1.	लाइफटाइम अचीवमेंट के लिये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार	1 पुरस्कार
2.	राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार	8 पुरस्कार (3 टीम पुरस्कार+3 संयुक्त पुरस्कार + 2 व्यक्तिगत पुरस्कार = 20 पुरस्कार विजेता)
3.	राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार	1 पुरस्कार
	कुल	**10 पुरस्कार (22 पुरस्कार विजेता)**

नोट :

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंडी फीचर फिल्म 'पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन' का प्रोमो तथा पोस्टर का विमोचन किया

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंडी फीचर फिल्म 'पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन' का प्रोमो तथा पोस्टर का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन की पुण्य तिथि पर उनका स्मरण करते हुए कहा कि लोग श्रीदेव सुमन के जीवन एवं कार्यों पर आधारित इस फिल्म के माध्यम से श्रीदेव सुमन को अनुभव करेंगे।
- श्रीदेव सुमन ने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई और तानाशाही के खिलाफ जनआंदोलन चलाए। अनेक अमानवीय यातनाओं को झेला, लेकिन सच्चाई के मार्ग से विचलित नहीं हुए।
- श्रीदेव सुमन केवल एक जननायक ही नहीं थे बल्कि उनके भीतर एक अटल देशभक्ति थी। वे एक क्रांतिकारी, बुद्धिजीवी, रचनाकार, पत्रकार एवं दूरदृष्टि की सोच रखने वाले महापुरुष थे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था तभी एक आंदोलन टिहरी प्रजामंडल के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका नेतृत्व श्रीदेव सुमन कर रहे थे। इस लड़ाई को लड़ते-लड़ते उन्होंने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किये, बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी, कई बार आमरण अनशन भी किया।
- उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और वर्षों तक जेल में रहे, जेल में उनके ऊपर अनेक अमानवीय अत्याचार हुये। इसके बावजूद भी उनका संघर्ष जारी रहा।
- उन्होंने 3 मई, 1944 को अपना ऐतिहासिक अनशन शुरू किया और 25 जुलाई, 1944 के शाम को उन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया।

नोट :

दून में 13 साल बाद होगी अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार अक्तूबर में होने वाली अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है। हालाँकि फिलहाल इसकी तिथि की घोषणा नहीं हुई है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि गृह मंत्रालय से इसके लिये पुलिस विभाग को पत्र मिल चुका है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। उत्तराखंड को 13 साल पहले 2010 में पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस की ज़िम्मेदारी मिली थी।
- विदित है कि पुलिस को आधुनिक अपराधों से लड़ने के लिये किस तरह से सक्षम बनाया जाए, इस पर मंथन के लिये देश में हर साल विज्ञान कॉन्ग्रेस आयोजित होती है। इसमें सभी राज्यों के आईजी और डीजीपी शिरकत करते हैं। पिछले साल यह विज्ञान कॉन्ग्रेस मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी।
- उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस के लिये अभी तक प्रदेश के देहरादून स्थित एफआरआई को आयोजन स्थल के लिये प्रस्तावित किया गया है। विज्ञान कांग्रेस में पैनल के लिये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।
- डीजीपी ने बताया कि इस बार विज्ञान कॉन्ग्रेस का मुख्य बिंदु ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, ड्रग्स तस्करी की रोकथाम होंगे। वर्तमान में साइबर क्राइम बड़ा अपराध है। इसमें अपराधी नए-नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इस पर विस्तार से चर्चा करना बेहद ज़रूरी है।

प्रदेश के सरकारी वाहनों के रखरखाव, मरम्मत व कंडम होने की स्थिति के संबंध में नया शासनादेश जारी

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड के परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने प्रदेश के सरकारी वाहनों के रखरखाव, मरम्मत व कंडम होने संबंधी पूर्व के सभी शासनादेशों को निष्क्रिय करते हुए नया शासनादेश जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- वाहनों की मरम्मत व निष्प्रयोज्य घोषित करने को लेकर पूर्व के सभी शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए नया शासनादेश जारी किया गया है। इस आधार पर ही मरम्मत व कंडम के नियम लागू होंगे।
- नये शासनादेश के तहत कोई भी 300 सीसी क्षमता से कम की सरकारी मोटरसाइकिल 10 साल की आयु और एक लाख किमी. चलने पर कंडम मानी जाएगी। सभी चौपहिया सरकारी वाहन 15 साल की आयु पूरी करने के बाद संचालित नहीं हो सकेंगे।
- वाहनों की मरम्मत के लिये परिवहन विभाग की ओर से अधिकृत गैराज या डीलर पर ही जा सकेंगे। जिन विभागों में वाहनों के रखरखाव व मरम्मत के लिये तकनीकी स्टाफ उपलब्ध है, वहाँ उपलब्ध बजट की सीमा में तकनीकी स्टाफ की संस्तुति के बाद विभागीय कार्यशालाओं में मरम्मत कराई जा सकती है।
- जिन विभागों में तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं है, वे परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक की तकनीकी सिफारिश के बाद परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त या अधिकृत गैराज या डीलर के पास मरम्मत करा सकते हैं। इसके लिये शर्त यह है कि वाहन के खरीद मूल्य का पाँच प्रतिशत से अधिक खर्च संभावित न हो।
- शासनादेश के मुताबिक, ऐसे वाहन, जिनकी आयु पूरी होने वाली हो और उनकी मरम्मत पर खर्च ज़्यादा आ सकता है, उनके लिये भी परिवहन विभाग निर्णय लेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें कंडम घोषित कर दिया जाएगा।

नोट :

- ये हैं वाहनों के कंडम होने के नियम:
  - सरकारी विभागों, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, राज्य परिवहन उपक्रम या किसी सार्वजनिक उपक्रम के सभी वाहन जिनकी आयु पंजीकरण की तिथि से 15 साल पूरी हो जाएगी, कंडम माने जाएंगे।
  - 300 सीसी से कम इंजन क्षमता के सरकारी दुपहिया वाहन पंजीकरण की तिथि से 10 साल की आयु पूरी करने और एक लाख किमी. (पर्वतीय क्षेत्र में 80 हज़ार किमी.) चलने पर कंडम किये जा सकते हैं।
  - 300 सीसी से अधिक क्षमता के सरकारी दुपहिया वाहन 10 साल आयु व 1.25 लाख (पर्वतीय क्षेत्र में एक लाख) किमी. चलने पर कंडम किये जा सकते हैं।
  - 12 साल की आयु और एक लाख किमी. चलने वाले सरकारी तिपहिया वाहन कंडम किये जा सकते हैं।
  - 3000 किलोग्राम तक सकल यानभार क्षमता वाले वाहन 13 साल की आयु व 1.50 लाख किमी. पर कंडम हो सकते हैं। 11 साल आयु व दो लाख किमी., नौ साल की आयु व 2.50 लाख किमी., सात साल की आयु व तीन लाख किमी. पर भी कंडम किये जा सकते हैं।
  - 3000-7000 किलोग्राम भार क्षमता वाले वाहन 12 साल की आयु व 2.25 लाख किमी., 10 साल की आयु व 2.75 लाख किमी. चलने पर कंडम हो सकते हैं।
  - 7500 किलोग्राम से अधिक क्षमता के वाहन 12 साल की आयु व 2.50 लाख किमी., 10 साल की आयु व तीन लाख किमी. के बाद कंडम हो सकते हैं।
  - अगर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और मरम्मत लायक स्थिति में न हो, तक्नीकी खराबी या वाहन संचालन व मरम्मत अधिक खर्चीला होने पर भी उसे संभागीय तकनीकी समिति की सिफारिश पर कंडम किया जा सकता है। इस समिति में संबंधित संभाग के आरटीओ, उपसंभाग के एआरटीओ, आरआई टेक्निकल शामिल होंगे।

गांवों के बच्चों को भी विज्ञान के प्रयोग करने का मिलेगा मौका, यूकॉस्ट भेजेगा मोबाइल साइंस लैब

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) के महानिदेशक डॉ. दुर्गेश पंत ने बताया कि प्रदेश के दुर्गम इलाकों के बच्चे भी अब विज्ञान के प्रयोग सीख सकेंगे। इसके लिये लैब्स ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में पहली बार हर ज़िले में यूकॉस्ट की मोबाइल वैन जाएगी, जिसमें लैब का पूरा साजो-सामान होगा।
- विदित है कि प्रदेश में तमाम विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ लैब्स तो हैं, लेकिन उतनी सुदृढ़ नहीं हैं, जितनी होनी चाहिये। कई जगहों पर तो बच्चे विज्ञान के प्रयोग भी नहीं कर पाते। खासतौर से आठवीं या 10वीं तक के बच्चे जो किताबें पढ़ते हैं, उनका वैज्ञानिक प्रयोग करने की व्यवस्थाएँ कमतर हैं। इस कमी को दूर करने के लिये ही यूकॉस्ट लैब्स ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू कर रहा है।
- जानकारी के मुताबिक, हर ज़िले में एक मोबाइल वैन संचालित की जाएगी। इस वैन में वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े हुए सभी उपकरण होंगे। एक-एक विशेषज्ञ की टीम भी साथ रहेगी। यह टीम दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँचकर बच्चों को विज्ञान के प्रयोग सिखाएगी। विज्ञान के चमत्कार बताएगी।
- यूकॉस्ट का मानना है कि इससे बच्चों के भीतर वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी।
- नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम (एनसीएसएम) की ओर से यूकॉस्ट झाझरा के बराबर में ही 25 एकड़ भूमि पर साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह अपनी तरह की सबसे अलग सिटी होगी, जिसमें जीवन के हर पहलू को विज्ञान के माध्यम से समझाया जाएगा। इस तरह की साइंस सिटी पूरे देश में चुनिंदा ही है।
- इसके अलावा, अल्मोड़ा में सब रीजनल साइंस सेंटर का निर्माण भी शुरू हो गया है। इसके लिये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पाँच करोड़ दिये हैं। इसे इसी साल से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

नोट :

राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के तहत गिद्धों की चार प्रजातियों पर होगा अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड वन विभाग के वाइल्ड लाइफ वार्डन चीफ डॉ. समीर सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में पहली बार राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के तहत गिद्धों की चार प्रजाति के दो-दो पक्षियों पर सैटेलाइट टैग लगाकर अध्ययन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- वाइल्ड लाइफ वार्डन चीफ ने बताया कि शिकारी श्रेणी का यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने इन्हें विलुप्तप्राय पक्षी की श्रेणी में रखा है।
- राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के तहत किये जाने वाले अध्ययन के लिये पक्षियों पर टैग लगाने के लिये वन विभाग ने शासन से अनुमति मांगी है।
- विदित है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गिद्धों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है, इसका ठीक-ठीक आँकड़ा किसी के पास नहीं है।
- वन विभाग की सांख्यिकी बुक में गिद्धों की संख्या का वर्ष 2005 का डाटा दर्शाया गया है। इसके अनुसार संरक्षित क्षेत्रों में गिद्धों की संख्या 1272 और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर 3794 कुल 5066 है।
- इसके बाद से यह डाटा अपडेट नहीं किया गया है। अब वन विभाग ने एक बार फिर से गिद्धों की दुनिया में झाँकने का बीड़ा उठाया है। इसके लिये डब्ल्यूडब्लयूएफ इंडिया के सहयोग से गिद्धों की चार प्रजातियों के दो-दो पक्षियों पर सैटेलाइट टैग लगाकर अध्ययन किया जाएगा।
- यह अध्ययन गढ़वाल में राजाजी टाइगर रिज़र्व और कुमाऊँ में कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के तहत किया जाएगा। इस अध्ययन में गिद्धों के रहवास, प्रवास, उनके रास्ते, रहन-सहन आदि के बारे में जानकारियाँ जुटाई जाएंगी।
- गिद्ध की इन प्रजातियों पर होगा अध्ययन:
  - लाल सिर गिद्ध (रेड हेडेड वल्चर)
  - सफेद पूँछ वाला गिद्ध (ह्वाइट रम्प्ड वल्चर)
  - सफेद गिद्ध (इजिप्सिन वल्चर)
  - प्लास फिश
- राजाजी टाइगर रिज़र्व के निदेशक और इस प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि यह चारों शिकारी प्रजाति के पक्षी बेहद दुर्लभ श्रेणी के हैं, लेकिन समय-समय पर उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊँ के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति पाई गई है। इनके संरक्षण को लेकर वन विभाग संजीदा है। इसी के तहत इन पर वृहद अध्ययन किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट अगले तीन साल तक चलेगा।

- यह चारों शिकारी पक्षी शेड्यूल वन प्रजाति के हैं। वन्यजीव अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में विशेष प्रयोजन के लिये अनुज्ञ पत्र का अनुदान की व्यवस्था है। ऐसे मामलों में शिक्षा, शोध, अनुसंधान इत्यादि के लिये राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है।

नोट :

ई-कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

- 29 जुलाई, 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आँकड़ों के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार पर्यावरण और समाज के लिये भविष्य में बड़े खतरे के तौर पर सामने आ रहे इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन, एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में 51541.12 मीट्रिक टन ई-कचरे को रिसाइकिल किया जा रहा है। यह आँकड़ा राज्य में ई-कचरे को रिसाइकिल करने की क्षमता से आधे से भी कम है। राज्य में 1.58 लाख मीट्रिक टन ई-कचरे के पुनर्चक्रण की क्षमता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आँकड़ों के आधार पर उत्तराखंड ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु सरीखे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा है।
- हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ई-कचरा एकत्र कर उसको रिसाइकिल करने के मामले में बहुत पीछे है।
- विदित है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिये ई-कचरा के एकत्रीकरण, प्रबंधन और पुनर्चक्रण हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ये दिशा-निर्देश विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादक, निर्माता, उपयोगकर्त्ता और पुनर्चक्रण एवं इसके थोक उपभोक्ता पर लागू होते हैं।
- ई-कचरा : ऐसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो काम नहीं कर रहे हैं या उपयोग के अपने अंतिम समय में हैं, जैसे- कंप्यूटर, टेलीविज़न, फोटो कॉपियर, फैक्स मशीन, विद्युत उपकरण, फ्रिज सरीखे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आदि ई-कचरा की श्रेणी में आते हैं।
- हिमालयी राज्य उत्तराखंड पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। ई-कचरा राज्य के लिये भविष्य की बहुत बड़ी चुनौती है। इसके गैर वैज्ञानिक ढंग से एकत्रीकरण करने, जलाने व बेतरतीब ढंग से जहाँ-तहाँ फेंकने से हवा और पानी के प्रदूषित होने का खतरा रहता है।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख सचिव (वन) व अध्यक्ष आर.के. सुधांशु ने बताया कि केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के आधार पर ई-कचरा प्रबंधन को लागू कर रहे हैं। सरकार की कोशिश यह रहेगी कि ई-कचरा के एकत्रीकरण को बढ़ाया जाए।
- इसके प्रभावी प्रबंधन के लिये आईटीडीए ई-कचरा प्रबंधन नीति बना रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नीति के संबंध में सुझाव दे दिये गए हैं।
- ई-कचरा एकत्र करने वाले शीर्ष 10 राज्य:
  1. हरियाणा - 245015.82 (मीट्रिक टन)
  2. उत्तराखंड - 51541.12
  3. तेलंगाना - 42297.68
  4. कर्नाटक - 39150.63
  5. तमिलनाडु - 31143.77
  6. गुजरात - 30569.32
  7. पंजाब - 28375.27
  8. राजस्थान - 27998.77
  9. महाराष्ट्र - 18559.30
  10. केरल - 1249.61

नोट :

उत्तराखंड/25 'बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच एक नई पहल' पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 29 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड/25 'बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच एक नई पहल' पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड के समग्र विकास हेतु पिछले एक वर्ष में बोधिसत्व विचार श्रृंखला के तहत आयोजित विभिन्न विषयों पर आधारित 12 सत्रों में वैज्ञानिकों, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधिसत्व विचार श्रृंखला के माध्यम से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की राह आसान बनाने का प्रयास रहा है। राज्य के विकास की दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिये सभी विभागों का 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अब तक 20 विभागों की समीक्षा की जा चुकी है।
- बोधिसत्व विचार श्रृंखला में प्राप्त सुझावों को इसमें शामिल किया जा रहा है। सरकार का प्रयास राज्य के विकास में
- सभी संस्थानों का सहयोग प्राप्त करने का रहा है। पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय को पशुपालन एवं कृषि विकास तथा
- तकनीकि विश्व विद्यालय को विज्ञान एवं तकनीकि का राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच बनाने में सहयोगी बनाया जाएगा।
- विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से उत्तराखंड/25 की अवधारणा के अनुरूप एक सशक्त, सक्षम एवं समृद्ध उत्तराखंड
- राज्य के निर्माण के लिये उन्होंने राज्य स्थित सभी प्रतिष्ठित संस्थानों की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा भी की।
- डिजिटल उत्तराखंड का उद्देश्य राज्य में रोज़गार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास में नए आयाम हासिल करना है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोलॉजी, इकोनॉमी, टैक्नोलॉजी, एकाउंटिबिलिटी और सस्टेनबिलिटी के पाँच सशक्त स्तंभों पर व्यवस्थित मॉडल उत्तराखंड/25 के संकल्प के लिये आवश्यक है। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड राज्य अपने सृजन की रजत जयंती वर्ष 2025 तक एक श्रेष्ठ राज्य बनकर उभरे तथा 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में समृद्ध और सशक्त रूप में स्थापित हो।

- यह बोधिसत्व विचार श्रृंखला ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों के संयोजन से आयोजित की गई।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधिसत्व का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्रित एक ऐसे मंच की स्थापना है जहाँ देश के मूर्धन्य मनीषी, वैज्ञानिक, युवा उद्यमी एवं जनप्रतिनिधि एक साथ एकत्र होकर राज्य के विकास के सभी आयामों पर गहन विचारविमर्श कर उत्तराखंड/25 की एक ऐसी कार्ययोजना तैयार कर सकें, जो राज्य का भविष्य उत्तरोत्तर स्वर्णिम बनाने में सहायक सिद्ध हो सके।
- इन श्रृंखलाओं से प्राप्त सुझावों को इस पुस्तक में समाहित किया गया है।

नोट :